



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग 30प्र०, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.- 4710,5149,5152,5161,

दिनांक :-

सेवा में,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

समस्त कोषागार को ई-मेल द्वारा भेजा गया।

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान।

महोदय,

इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियां प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार संबंधित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय / दर / प्रभावी तिथि	शासनादेश का सन्दर्भ
1	CHHATTISGARH	सातवाँ वेतन 01/03/2024 से देय मंहगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 4% वृद्धि उपरान्त मंहगाई राहत का प्रतिशत 46% छठवाँ वेतनमान 01/03/2024 से देय मंहगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 9% वृद्धि उपरान्त मंहगाई राहत का प्रतिशत 230%	G.O. 144/F-2013-04-00416/ Fin/Rule/IV, दिनांक 15.03.2024
2	ANDHRA PRADESH	Dearness relief to the Judicial Pensioners/ Family pensioners with effect from 01-07-2023 (42% to 46%) Dearness relief to the Pensioners/ Family pensioners w.e.f. 01.01.2023 (26.39% to 30.03%) & Dearness relief to the Pensioners/ Family pensioners w.e.f. 01.07.2023 (30.03% to 33.67%) Sanctioned- Order-Issued.	G.O. Ms. No.- 26, Dated 14.03.2024, G.O. Ms. No.- 29, Dated 16.03.2024, G.O. Ms. No.- 31, Dated 16.03.2024,
3	UTTARAKHAND	1- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को दिनांक 01 जुलाई 2023 से बढ़ी हुई दर (42% से 46%) पर मंहगाई भत्ते का भुगतान। 2- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत (42% से 46%) की स्वीकृति। 3- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को दिनांक 01 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर (46% से 50%) पर मंहगाई भत्ते का भुगतान। 4- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत (46% से 50%) की स्वीकृति।	1- G.O No.उत्तराखण्ड शासन वित्त)वे०-आ 0सा०-नि (0अनुभाग 7-संख्या-182100/XXVII(7)E-22807/2022 देहरादून, दिनांक 13/01/2024 2- G.O No.उत्तराखण्ड शासन वित्त)सा०-नि०-वे०-आ (0अनुभाग 7-संख्या-182101/XXVII(7)E-22807/2022 देहरादून, दिनांक 13/01/2024 3- G.O No.उत्तराखण्ड शासन वित्त)वे०-आ 0सा०-नि (0अनुभाग 7-संख्या-199033/XXVII(7)E-22807/2022 देहरादून, दिनांक 14/03/2024 4- G.O No.उत्तराखण्ड शासन वित्त)सा०-नि०-वे०-आ (0अनुभाग 7-संख्या-199032/XXVII(7)E-22807/2022 देहरादून, दिनांक 14/03/2024

4	MEGHALAYA	Grant of Dearness Relief to State Govt. Pensioners/ Family Pensioners of Govt. of Meghalaya, From the existing rate of 39% to 43% w.e.f. 01.01.2024	G.O.No.-F(PR)-53/2017/66 Dated 23.02.2024
---	-----------	---	--

आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, संबन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें। उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी प्रति प्रेषित करें।

भवदीय



वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन

No. Pension(Misc)/

Dated :-

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	Office of The Principal Accountant General (A&E)-II, Chhattisgarh, Zero point Baloda Bazar Road, Raipur-492005
2	PAG (A&E) Andhra Pradesh, Stalin Central Mall, 7th floor, M.G. Road, Governor Pet, Vijayawada, Andhra Pradesh - 520002
3	AG(A&E) Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun-248195
4	Office of the Principal Accountant General (A&E)- Meghalaya, M.G.Road opposite Governor House, Shillong. 793001
5	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10 th Floor, Lucknow 226001
6	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
7	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
8	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
9	Sr. Accounts Officer, Computer Cell , O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन



EC 32493600 FIA

SSDR/12
18/04/24

क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./28
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

प्रति,

दिनांक 04.04.2024
Date

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Nahariagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीविशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) माणपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102

जीरो पॉइन्ट, बलोदा बाजार रोड, रायपुर - 492005, दूरभाष : + 91-771-2285954, पी.बी.एक्स : 2281451, फैक्स : + 91-771-2282607
ZERO POINT, BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR-492005 Tel.: + 91-2285954, P.B.X. : 2281451, Fax : +91-771 - 2282607
ई-मेल / E-mail : agChattisgarh@cag.gov.in, agaechhattisgarh@cag.gov.in

24.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकर (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ओ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकर (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहारादून आंबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
27.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकर (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.03.2024 से सातवें वेतनमान में 46% एवं छठवें वेतनमान में 230% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में
संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 144/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 15.03.2024.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

पू.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

प्रतिलिपि:

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 166/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 19.03.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA

MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No. 144/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated .03.2024
To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners

The State Government had sanctioned 42% (in Seventh Pay Scale) and 221% (in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.07.2023 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 541/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 31-08-2023.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

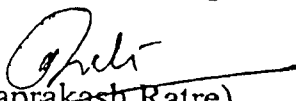
Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-03-2024	4% of Basic Pension/ Family Pension	46%
Sixth Pay Scale	01-03-2024	9% of Basic Pension/ Family Pension	230%

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.

F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV /2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).
5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.
6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(Indraprakash Ratre)
Under Secretary



515750551211

प्रधानमहालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी)

आंध्रा प्रदेश, विजयवाड़ा - 520002

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH, VIJAYAWADA - 520002

PAG (A&E)/AP/OGP/2024-25/342613
Under Special Seal Authorisation No. 16690

Date: 08.04.2024

To
The Accountant General (A&E)-II,
Uttar Pradesh, Prayagraj 20
Sarojini Naidu Marg, Prayagraj
Uttar Pradesh – 211 001.

Sir/Madam,

- Sub: 1. Pensions – DR (42% to 46%) to Judicial Pensioners/Family Pensioner's w.e.f. 01.07.2023 – Orders - Issued.
2. Pensions – DR (26.39% to 30.03%) to the Pensioners/Family Pensioner's w.e.f. 01.01.2023 – Orders – Issued.
3. Pensions – DR (30.03% to 33.67%) to the Pensioners/Family Pensioner's w.e.f 01.07.2023 – Orders – Issued.

- Ref: 1. Govt. of AP G.O.Ms.No.26, dated 14.03.2024.
2. Govt. of AP G.O.Ms.No.29, dated 16.03.2024.
3. Govt. of AP G.O.Ms.No.31, dated 16.03.2024.

I am to forward herewith a copies of Finance (HR-III-Pension, GPF) Department G.O.Ms.No.26 dated 14.03.2024, G.O.Ms. No.29 dated 16.03.2024 and G.O.Ms. No.31 dated 16.03.2024 of Government of Andhra Pradesh regarding subject cited.

The same are placed at the office website www.agaepts.gov.in. You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the order and take necessary action at the earliest.

Encl: As above

Yours faithfully

G. K. K. K.
8/4

Sr. Accounts Officer

Email : agaeandhrapradesh@cag.gov.in
Website : <http://agaepts.gov.in>

SCANNED

प्रधान महासचिव (न. एवं ह.) का कार्यालय
Office of the P.H. Accountant General (A&E)
INWARD
21 MAR 2024
No.

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
ABSTRACT

अंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा
Andhra Pradesh, Vijayawada-52

Pensions - Dearness Relief - Dearness Relief to the Judicial Pensioners/Family Pensioners with effect from 01-07-2023 - Sanctioned - Orders - Issued.

FINANCE (HR.III-Pension, GPF) DEPARTMENT

G.O. Ms. No.26

Dt:14-03-2024

Read the following:-

- 1.G.O.Ms.No.2, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 17.01.2022.
- 2.G.O.Ms.No.9, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 17.01.2022.
- 3.G.O.Ms.No.115, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 03.06.2022.
- 4.G.O.Ms.No.67, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 01.05.2023.
- 5.G.O.Ms.No.115, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 22.10.2023.
6. G.O.Ms.No.126, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 01-12-2023.

ORDER:

In the reference 1st read above, Government have issued comprehensive orders, for Revision of Pay Scales, 2022 to the retired employees (Pensioners/Family pensioners) of Government of Andhra Pradesh.

2. In the reference 2nd read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) for the period from 01.07.2019 to 31.12.2021 to the pensioners/family pensioners including Judicial pensioners/ Family pensioners.

3. In the reference 3rd read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) in respect of Pensioners /Family Pensioners, drawing their pay in the Revised UGC Pay Scales, 2006 and the Judicial Pensioners/Family Pensioners whose pay was revised as per Sri Padmanabhan Committee Report vide the G.O. Ms. No.73, Law (LA&J, SCF) Department, dated 01.05.2010 with effect from 01.07.2021.

4. In the reference 4th and 5th read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) with effect from 01.01.2022 & 01-07-2022 in respect of Pensioners /Family Pensioners including Judicial pensioners/Family pensioners.

5. In the reference 6th read above, Government have issued orders for the revision of rates of Dearness Relief in respect of Judicial Pensioners/Family

Pensioners whose pay scales were revised as per Second National Judicial Pay Commission, vide G.O.Ms.No.58, Law (LA&J SC-F) Department, dated 22.10.2022 and vide G.O.Ms.No.73, Law (LA&J SC-F) Department, dated 01.05.2010, from 38% to 42% of the Basic Pension and from 212% to 221% of the Basic Pension with effect from 01.01.2023 respectively.

6. Government hereby order the revision of rates of Dearness Relief in respect of Judicial pensioners/Family pensioners whose pay scales were revised as per Second National Judicial Pay Commission, vide G.O.Ms.No.58, Law(LA&J SC-F) Department, dated 22.10.2022, from 42% to 46% of the Basic Pension with effect from 01.07.2023.

7. Government also hereby order the revision of rates of Dearness Relief in respect of Judicial pensioners/Family pensioners whose pay scales were revised as per Shri Padmanabhan Committee Report, vide G.O.Ms.No.73, Law(LA&J SC-F) Department, dated 01.05.2010 from 221% to 230% of the Basic Pension with effect from 01.07.2023.

8. The Dearness Relief sanctioned in the above paras, shall be paid with pension of March, 2024 payable in April, 2024. The arrears on account of increase of Dearness Relief for the period from 01.07.2023 to 29.02.2024 shall be paid in the month of April, 2024.

9. All the Treasury Officers/ Pension Payment Officers shall work out and make payments of the Dearness Relief on Pension sanctioned in this order without waiting for further authorization/ instructions from the Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Vijayawada in terms of the orders issued in the G.O.Ms.No.270, Finance & Planning (FW: PSC.I) Department, dated.07.10.1986.

10. All the Treasury Officers/Pension Payment Officers shall work out and make payments of the dearness relief on pension sanctioned in this order in terms of orders issued in the G.O.Ms.No.122, Finance (Pen.I) Department, Dt: 22.05.2014.

11. The expenditure is allocable among the various States in accordance with provisions of Rule 24 of the incidence of Pension Rules in Appendix III-B of the Andhra Pradesh Accounts Code, Volume-I.

12. The CEO, APCFSS is directed to develop a software module to calculate the DR arrears and generate due drawn statement to facilitate generation of DR arrears bills by the Drawing & Disbursing Officers.

13. The G.O is available on Internet and can be accessed at the address <http://apgazette.egg.gov.in>

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)

CHIRANJIV CHOUDHARY
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT (HR)

To

The Registrar, High Court of Andhra Pradesh, Amaravati.

The Principal Secretary to Governor of Andhra Pradesh, Vijayawada.

The Principal Secretary / Secretary to the Chief Minister & Private Secretaries to all Ministers.

The A.G (A&E) / ~~Pr.~~ A.G. (G&SSA) / A.G.(E&RSA), A.P., Vijayawada.

The Director of Treasuries & Accounts, AP, Mangalagiri.

The Director of State Audit, A.P., Mangalagiri.

The Pay & Accounts Officer, A.P., Mangalagiri.

The Director of Works Accounts, A.P., Mangalagiri.

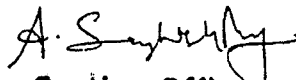
All the District Treasury Officers.

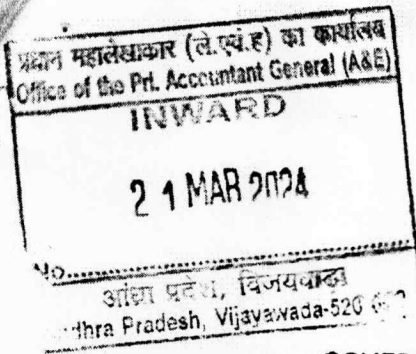
Copy to

The General Administration (Cabinet) Department.

S.F. /S.Cs. (Computer No. 2120775).

./Forwarded By:: Order//


Section Officer



625866
25/3/24

SCANNED

Page | 1

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
ABSTRACT

Pensions - Dearness Relief - Dearness Relief (DR) to Pensioners/Family Pensioners with effect from 01-01-2023 - Sanctioned - Orders - Issued.

FINANCE (HR.III-Pension, GPF) DEPARTMENT

G.O.Ms.No.29

Date: 16.03.2024.
Read the following:-

1. G.O.Ms.No.2, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 17.01.2022.
2. G.O.Ms.No.9, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 17-01-2022.
3. G.O.Ms.No.115, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 03-06-2022.
4. G.O.Ms.No.67, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 01-05-2023.
5. G.O.Ms.No.115, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 22-10-2023
6. Ministry of Finance, Department of Exp. Govt. of India, No.1/1/2023-EII(B) dated 03-04-2023.
7. Ministry of Finance, Dept. of Exp. Govt. of India, No.1/3(1)/2008-E-II(B) dated 10-04-2023.
8. G.O.Ms.No.28, Finance (PC-TA) Department, dated 16-03-2024.

ORDER:

In the reference 1st read above, Government have issued comprehensive orders, for Revision of Pay Scales, 2022 for the retired employees (Pensioners/Family pensioners) of Government of Andhra Pradesh.

2. In the reference 2nd read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) for the period from 01-07-2019 to 31-12-2021 for the pensioners/family pensioners.

3. In the reference 3rd read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) in respect of Pensioners/Family Pensioners, drawing their pay in the Revised UGC Pay Scales, 2006 and the Judicial Pensioners/Family Pensioners whose pay was revised as per Sri Padmanabhan Committee Report vide the G.O. Ms. No.73, Law (LA&J, SCF) Department, dated 01-05-2010 with effect from 01-07-2021.

4. In the reference 4th read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) with effect from 01-01-2022 in respect of Pensioners/Family Pensioners.

5. In the reference 5th read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) from 22.75% to 26.39% with effect from 01-07-2022 in respect of Pensioners/Family Pensioners.

6. In the reference 8th read above, Government have issued orders for the revision of Dearness Allowance (DA) for the employees of Government of Andhra Pradesh, from 26.39% to 30.03% of the Basic Pay with effect from 01-01-2023.

7. Government, hereby orders the revision of the Dearness Relief (DR) sanctioned in the Government orders 5th read above for the Pensioners/Family Pensioners, from 26.39% to 30.03% of the Basic pension with effect from 01-01-2023 in respect of:

- a. Those who retired from service after 01-07-2018 and drawing pension in the Revised Pay Scales, 2022;
- b. Those who retired prior to 01-7-2018 and whose pension was consolidated in the light of orders issued in the G.O.1st read above.

8. Government, also hereby orders to revise the rates of Dearness Relief with effect from 01-01-2023 to various categories of pensioners in the State w.r.to 6th & 7th read above, as indicated below:

Sl. No.	Category	Existing Rate (%)	Revised Rate (%)
1	UGC/AICTE Pensioners/Family Pensioners drawing UGC Pay Scales 2006.	212	221
2	UGC/AICTE Pensioners/Family Pensioners-drawing UGC Pay Scales 2016	38	42

9. These orders are applicable to:

1. a. All Government Pensioners in receipt of Service Pensions, Family Pensions under Revised Pension Rules, 1951, Andhra Pradesh Liberalized Pension Rules, 1961 and Andhra Pradesh Government Servants (Family Pension) Rules, 1964.
- b. Teaching and Non-Teaching pensioners of Municipalities, Panehayat Raj Institutions and Aided Educational Institutions, in receipt of pensions under the Andhra Pradesh Liberalized Pension Rules, 1961 and Andhra Pradesh Government Servants (Family Pension) Rules, 1964.
- e. Teaching and Non-Teaching staff in Aided Educational Institutions in receipt of pensions under the Contributory Provident Fund-cum- Pension and Gratuity Rules, 1961 and Andhra Pradesh Liberalized Pension Rules, 1961.
- d. Those drawing family pensions under G.O.Ms.No.22, Finance & Planning (FW: Pen.I) Department, dated 16-01-1971, G.O.Ms. No.104, Finance & Planning (FW: Pen.I) Department, dated 13- 4-1973 and G.O.Ms.No.25, Finance & Planning (FW:Pen.I) Department, dated 2-2-1974.
- e. Pensioners in receipt of Compassionate Pension under the rules for Compassionate Pensions and Gratuities in the Hyderabad Civil Services Rules; and

The Director of Treasuries and Accounts, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Director of State Audit, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Director of Works and Accounts, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Pay and Accounts Officer, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Principal Accountant General (A&E) A.P. Stallin Road, Vijayawada.
The Principal Accountant General (G&SSA) A.P. Vijayawada.
The Principal Accountant General (E&RSA) A.P., Vijayawada.
The Accountant General of other states given below through A.G., A.P.
Vijayawada (50 copies)
The Accountant General, Tamilnadu, Chennai.
The Accountant General, Maharashtra, Mumbai.
The Accountant General, Gujarat.
The Account General (A&E) Kerala, P.N.No.5607
Tiruvananthapuram - 695039.
The Accountant General (A&E) Karnataka, Bangalore.
The Accountant General (A&E), U.P., Allahabad.

//FORWARDED::BY ORDER//

N. Praveen
SECTION OFFICER

f. Those in receipt of Pensions under the Wound and Extraordinary Pension Rules.

2. Pensioners governed by Andhra Pradesh Revised Pension Rules, 1980.

10. These orders are not applicable to the financial assistance grantees and others who are not entitled for Dearness Relief.

11. The Dearness Relief sanctioned in above paras shall be paid with pension of April 2024, payable in May 2024. The arrears on account of increase of DR for the period from 01-01-2023 to 31-03-2024 shall be paid in three (3) equal installments in August 2024, November 2024 & February 2025.

12. All the Treasury Officers / Pension Payment Officers shall work out and make payments of the Dearness Relief on Pension sanctioned in this order without waiting for further authorization/ instructions from the Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Vijayawada in terms of the orders issued in the G.O.Ms.No.270, Finance & Planning (FW:PSC.I) Department, dated 7-10-1986.

13. All the Treasury Officers / Pension Payment Officers shall calculate and make payments of the dearness relief on pension sanctioned in this order in terms of orders issued in the G.O.Ms.No.122, Finance (Pen.I) Department, dated 22-05-2014.

14. The expenditure is allocable among the various States in accordance with provisions of Rule 24 of the incidence of Pension Rules in Appendix III-B of the Andhra Pradesh Accounts Code, Volume-I.

15. In respect of the categories of employees who are not covered for payment through the Treasuries, the expenditure shall be debited to the Pension Fund of Zilla Parishad and Pension Fund of the respective Municipal Councils.

16. In respect of the Pensioners of the Universities, the expenditure on account of the Dearness Relief now sanctioned above shall be met from the Block Grants allotted to them.

17. The CEO, APCFSS is directed to develop a software module to calculate the DA/DR arrears and generate due drawn statement to facilitate generation of DA/DR arrears bills by the Drawing & Disbursing Officers.

18. The G.O is available on Internet and can be accessed at the address <http://apgazette.egg.gov.in>.

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)

SHAMSHER SINGH RAWAT
SPECIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT

To
All Departments of Secretariat.
All Heads of Departments.

PMI
625826
25/3/24

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సర్కారు Office of the Accountant General (A.G.)
INWARD
22 MAR 2024
No.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్, విజయవాడ Andhra Pradesh, Vijayawada-520 002

SCANNED

Page | 1

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
ABSTRACT

Pensions - Dearness Relief - Dearness Relief (DR) to Pensioners/Family Pensioners with effect from 01-07-2023 - Sanctioned - Orders - Issued.

FINANCE (HR.III-Pension, GPF) DEPARTMENT

G.O.Ms.No. 31

Date: 16.03.2024.
Read the following:-

1. G.O.Ms.No.2, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 17-01-2022.
2. G.O.Ms.No.9, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 17-01-2022.
3. G.O.Ms.No.115, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 03-06-2022.
4. G.O.Ms.No.67, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 01-05-2023.
5. G.O.Ms.No.115, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 22-10-2023
6. Ministry of Finance, Department of Exp. Govt. of India, No.1/1/2023-EII (B) dated 03-04-2023.
7. Ministry of Finance, Dept. of Exp. Govt. of India, No.1/3(1)/2008-E-II(B) dated 10-04-2023.
8. G.O.Ms.No.29, Finance (HR.III-Pension, GPF) Department, dated 15-03-2024.
9. G.O.Ms.No. 30, Finance (PC-TA) Department, dated 15-03-2024

ORDER:

In the reference 1st read above, Government have issued comprehensive orders, for the Revision of Pay Scales, 2022 of the retired employees (Pensioners/Family pensioners) of Government of Andhra Pradesh.

2. In the reference 2nd read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) for the period from 01-07-2019 to 31-12-2021 for the pensioners/family pensioners.

3. In the reference 3rd read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) in respect of Pensioners/Family Pensioners, drawing their pay in the Revised UGC Pay Scales, 2006 and the Judicial Pensioners/Family Pensioners whose pay was revised as per Sri Padmanabhan Committee Report vide the G.O. Ms. No.73, Law (LA&J, SCF) Department, dated 01-05-2010 with effect from 01-07-2021.

4. In the reference 4th read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) with effect from 01-01-2022 in respect of Pensioners/Family Pensioners.

5. In the reference 5th read above, Government have issued orders for release of Dearness Relief (DR) from 22.75% to 26.39% with effect from 01-07-2022 in respect of Pensioners/Family Pensioners.

The Director of Treasuries and Accounts, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Director of State Audit, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Director of Works and Accounts, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Pay and Accounts Officer, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Principal Accountant General (A&E) A.P. Stallin Road, Vijayawada.
The Principal Accountant General (G&SSA) A.P. Vijayawada.
The Principal Accountant General (E&RSA) A.P., Vijayawada.
The Accountant General of other states given below through A.G., A.P.
Vijayawada (50 copies)
The Accountant General, Tamilnadu, Chennai.
The Accountant General, Maharashtra, Mumbai.
The Accountant General, Gujarat.
The Account General (A&E) Kerala, P.N.No.5607
Tiruvananthapuram - 695039.
The Accountant General (A&E) Karnataka, Bangalore.
The Accountant General (A&E), U.P., Allahabad.

//FORWARDED::BY ORDER//

N. Prasad
SECTION OFFICER

6. In the reference 8th read above, Government have issued orders for the revision of Dearness Relief (DR) to the Pensioners of Government of Andhra Pradesh, from 26.39% to 30.03% of the Basic Pay with effect from 01-01-2023.

7. In the reference 9th read above, Government have issued orders for the revision of Dearness Allowance (DA) to the employees of Government of Andhra Pradesh, from 30.03% to 33.67% of the Basic Pay with effect from 01-01-2023.

8. Government, hereby orders the revision of the Dearness Relief (DR) sanctioned in the Government order 8th read above for the Pensioners/Family Pensioners, from 30.03% to 33.67% of the Basic pension with effect from 01-07-2023 in respect of:

- a. Those who retired from service after 01-07-2018 and drawing pension in the Revised Pay Scales, 2022;
- b. Those who retired prior to 01-7-2018 and whose pension was consolidated in the light of orders issued in the G.O.1st read above.

9. Government, also hereby orders to revise the rates of Dearness Relief with effect from 01-07-2023 to various categories of pensioners in the State w.r.t to the references 6th & 7th read above, as indicated below:

Sl. No.	Category	Existing Rate (%)	Revised Rate (%)
1	UGC Pensioners/Family Pensioners drawing UGC Pay Scales 2006.	221	230
2	UGC Pensioners/Family Pensioners-drawing UGC Pay Scales 2016	42	46

10. These orders are applicable to:

1. a. All Government Pensioners in receipt of Service Pensions, Family Pensions under Revised Pension Rules, 1951, Andhra Pradesh Liberalized Pension Rules, 1961 and Andhra Pradesh Government Servants (Family Pension) Rules, 1964.
- b. Teaching and Non-Teaching pensioners of Municipalities, Panchayat Raj Institutions and Aided Educational Institutions, in receipt of pensions under the Andhra Pradesh Liberalized Pension Rules, 1961 and Andhra Pradesh Government Servants (Family Pension) Rules, 1964.
- e. Teaching and Non-Teaching staff in Aided Educational Institutions in receipt of pensions under the Contributory Provident Fund-cum- Pension and Gratuity Rules, 1961 and Andhra Pradesh Liberalized Pension Rules, 1961.
- d. Those drawing family pensions under G.O.Ms.No.22, Finance & Planning (FW: Pen.I) Department, dated 16-1-1971, G.O.Ms.No.104, Finance & Planning

(FW: Pen.I) Department, dated 13-4-1973 and G.O.Ms.No.25, Finance & Planning (FW:Pen.I) Department, dated 2-2-1974.

e. Pensioners in receipt of Compassionate Pension under the rules for Compassionate Pensions and Gratuities in the Hyderabad Civil Services Rules; and

f. Those in receipt of Pensions under the Wound and Extraordinary Pension Rules.

2. Pensioners governed by Andhra Pradesh Revised Pension Rules, 1980.

11. These orders are not applicable to the financial assistance grantees and others who are not entitled for Dearness Relief.

12. The Dearness Relief sanctioned in above paras shall be paid with pension of July 2024, payable in August 2024. The arrears on account of increase of DR for the period from 01-07-2023 to 30-06-2024 shall be paid in three (3) equal installments in September 2024, December 2024 & March 2025.

13. All the Treasury Officers/ Pension Payment Officers shall calculate and make payments of the Dearness Relief on Pension sanctioned in this order without waiting for further authorization/ instructions from the Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Vijayawada in terms of the orders issued in the G.O.Ms.No.270, Finance & Planning (FW:PSC.I) Department, dated 7-10-1986.

14. All the Treasury Officers/Pension Payment Officers shall calculate and make payments of the dearness relief on pension sanctioned in this order in terms of orders issued in the G.O.Ms.No.122, Finance (Pen.I) Department, dated 22-05-2014.

15. The expenditure is allowable among the various States in accordance with provisions of Rule 24 of the incidence of Pension Rules in Appendix III-B of the Andhra Pradesh Accounts Code, Volume-I.

16. In respect of the categories of employees who are not covered for payment through the Treasuries, the expenditure shall be debited to the Pension Fund of Zilla Parishad and Pension Fund of the respective Municipal Councils,

17. In respect of the Pensioners of the Universities, the expenditure on account of the Dearness Relief now sanctioned above shall be met from the Block Grants allotted to them.

18. The CEO, APCFSS shall develop make necessary provision in the CFMs software to calculate the DA/DR arrears and generate due drawn statement to facilitate generation of DA/DR arrears bills by the Drawing & Disbursing Officers.

19. The G.O is available on Internet and can be accessed at the address <http://apgazette.egg.gov.in>.

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)

SHAMSHER SINGH RAWAT
SPECIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT

To
All Departments of Secretariat.
All Heads of Departments.
The Director of Treasuries and Accounts, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Director of State Audit, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Director of Works and Accounts, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Pay and Accounts Officer, A.P., Mangalagiri, Guntur District.
The Principal Accountant General (A&E) A.P. Stallin Road, Vijayawada.
The Principal Accountant General (G&SSA) A.P. Vijayawada.
The Principal Accountant General (E&RSA) A.P., Vijayawada.
~~The~~ Accountant General of other states given below through A.G., A.P.
Vijayawada (50 copies)
The Accountant General, Tamilnadu, Chennai.
The Accountant General, Maharashtra, Mumbai.
The Accountant General, Gujarat.
The Accountant General (A&E) Kerala, P.N.No.5607 Tiruvananthapuram-695039.
The Accountant General (A&E) Karnataka, Bangalore.
The Accountant General (A&E), U.P., Allahabad.
The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
The Accountant General (A&E), Punjab, Chandigarh.
The Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur.
The Accountant General (A&E), Assam, Dispur.
The Accountant General (A&E), Bihar, Patna.
The Accountant General, Orissa, Bhubaneswar.
The Accountant General, (A&E-II), Madhya Pradesh, Gwalior.
The Accountant General (Pen.Co-Ordination), O/o the Principal Accountant General (A&E) Calcutta, West Bengal.
The Secretary to Government, Finance Department, Secretariat, Chennai, Tamilnadu.
The Secretary to Government, Finance Department, Secretariat, Trivandrum, Kerala.
The Secretary to Government, Finance Department, Secretariat, Bhubaneswar, Orissa.
The Public Accounts Officer, Treasury, Pondicherry.
The Principal Secretary to Governor, Raj Bhavan, Vijayawada.
The Registrar General, High Court of Andhra Pradesh & Nelapadu.
The Registrar Lokayukta and Upa Lokayukta, A.P. Kurnool.
The Principal Secretary, Andhra Pradesh Public Service Commission, Vijayawada.
The Managing Director, A.P. GENCO, Vidyut Soudha, Vijayawada.

The Managing Director, A.P. TRANSCO, Vidyut Soudha, Vijayawada.
All the District Collectors in Andhra Pradesh.
All the District Judges in Andhra Pradesh
All the District Treasury Officer in Andhra Pradesh.
All the Chief Executive Officer of Zilla Praja Parishad in Andhra Pradesh.
All the District Panchayat Officer in Andhra Pradesh
All the District Educational Officer in Andhra Pradesh.
All the Commissioners/Special Officer of Municipalities/Municipal Corporations in A.P.
The Registrars of all the Universities in Andhra Pradesh.
The Secretary Tungabhadra Project, Via. Hospet, Ballary District.
The Director of State Ports, Kakinada, East Godavari, A.P.,
All the Secretaries, Agricultural Market Committees through Commissioner
& Director of Agriculture Marketing (30 Copies).
The Resident Commissioner, A.P. Bhavan, Ashoka Road, New Delhi-110001.
The Pay & Accounts Officer, Government of Andhra Pradesh, New Delhi-110001
All the Pensioners Associations in Andhra Pradesh.
SF/SC's. (Computer No. 2385716)

//FORWARDED::BY ORDER//

N. P. S. Reddy
SECTION OFFICER

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

सेवा में,

दिनांक 04/04/2024

EV 3206083641

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781005
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुंबई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड

"महालेखाकार भवन" कौलागढ देहरादून-248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 23-24/

दिनांक: 10/4/ 2024

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय

विषय-1. राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

विषय-2. राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

विषय-3. राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

विषय-4. राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संदर्भ:- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 199033/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 14.03.2024।

संदर्भ:- (2) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 199032/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 14.03.2024।

संदर्भ:- (3) अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 182100/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 13.01.2024।

संदर्भ:- (4) अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 182101/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 13.01.2024।

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या-182100/XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून, दिनांक: 13 जनवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक: 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-126937/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक: 02 जून 2023 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक: 01 जनवरी, 2023 से 42% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
- 2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-114/2023-11(B) दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 46% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- 3 यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
4. उक्त कार्मिकों को दिनांक: 01 जुलाई, 2023 से दिनांक: 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।
5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

Signed by Ganga Prasad
Date: 13-01-2024 10:45:53

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या-182100(1)/XXVII(7)/E-22807/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध

FIN-7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department

1/182100/2024 में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्वन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें उत्तराखण्ड।
14. सहायक निदेशक आयुक्त देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
16. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।



(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

1/182101/2024

FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सांनिधि-वेतन) अनुभाग-7
संख्या-182101/XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून दिनांक: 13 जनवरी, 2024

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No-182101/XXVII(7)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 13 January, 2024

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-126934/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-07-2023 से 42 प्रतिशत के स्थान पर 48 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महाराज की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2023 @ 46% instead of 42 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 126934/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 02 Jun, 2023 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश माओ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणरत पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Signed by Ganga Prasad
Date: 13-01-2024 10:52:06

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.

संख्या-182101/XXVII(7)/E-22807/2022, तद्विनांक।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

No. 182101(3)/XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.
Copy forwarded to following for information and
necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम
विकास विभाग/राष्ट्रीय विकास विभाग, उत्तराखण्ड
शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम
की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए
निकाय/उपक्रम के कार्यों को महंगाई राहत
अनुमत्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले
सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति
की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,
देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस
आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा
प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का
कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड,
डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को
इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश
की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7,
उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaries/Principal
Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public
Industry Development Department/Urban
Development, Govt. of Uttarakhand with the
request that the admissibility of dearness relief
may be permitted itself in the view of financial
status of the bodies undertaking and there is no
need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate,
Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments/Offices,
Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand,
Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun
along with 50 extra copies with the request that
account officers of other states be also informed
please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hakdari,
Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi
Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury
Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with
request that 50 copies of this G.O. be got printed
and sent to the Finance Section-7, Govt. of
Uttarakhand Please.

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.

2366

21/3/24

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

संख्या: 199033/XXVII(7)/E-22807/2022

देहरादून, दिनांक: 14 मार्च, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक: 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 182100/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक: 13 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक: 01.07.2023 से 46% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/1/2024-ई.-II(बी) दिनांक: 12.03.2024 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक: 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46% को बढ़ाकर 50% प्रतिमाह किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2024 से 29.02.2024 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01.03.2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

21/03/24

AMM/T.M

Sh. Mukul, Accountant

सचिवालय महालेखाकार
आवृत्ति सं. 2937
दिनांक 17 MAR 2024
उत्तराखण्ड, देहरादून

20 MAR 2024
13019
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 14-03-2024 19:08:23

04/04/24
TM

दिलीप जावलकर
सचिव।

संख्या: 199033 (1)/XXVII(7)/E-22807/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपमहालेखाकार/निबि प्रकाश
ए.जी.डी.ए.जी. आवृत्ति संख्या 2900
दिनांक: 26/03/24

DL-01
4/4/24

199033/2-4 प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उ
शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत
हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने
सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति
की आवश्यकता नहीं होगी।

6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad

Date: 14-03-2024 19:19:2

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या: 199032/XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून: दिनांक: 14 मार्च, 2024

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No-199032/XXVII(7)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 14 March, 2024

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Office Memorandum
Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-182101/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक: 13 जनवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01-01-2024 से 46% प्रतिशत के स्थान पर 50% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2024 @ 50% instead of 46% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 182101/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 13 January, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 14-03-2024 19:05:58

(Dilip Jawalkar)
Secretary.

संख्या-199032/XXVII-7-22807/2012, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम
विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम
की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए
निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत
अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले
सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति
की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,
देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस
आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा
प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला,
देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय - लेखा, 23 लक्ष्मी रोड,
डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस
आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की
50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7,
उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

No.199032/XXVII-7-22807/2012, the dated.

Copy forwarded to following for information and
necessary action.

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaries/ Principal
Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public
Industry Development Department/Urban
Development, Govt. of Uttarakhand with the
request that the admissibility of dearness relief
may be permitted itself in the view of financial
status of the bodies/undertaking and there is no
need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate,
Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices,
Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand,
Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun
along with 50 extra copies with the request that
account officers of other states be also informed
please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari,
Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi
Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury
Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with
request that 50 copies of this G.O. be got printed
and sent to the Finance Section-7, Govt. of
Uttarakhand Please.

By Order,

Signed by Ganga Prasad

Date: 14-03-2024 19:18:29

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.

REGISTERED



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (ले. व. ह.), मेघालय, शिलांग - 793 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
MEGHALAYA, SHILLONG-793 001

फैक्स संख्या/Fax No. 0364 -2223103 ई-मेल/E-mail:
agaemeghalaya@cag.gov.in

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY

Letter No./पत्र संख्या: Pension(M)1/T-10/DR/MEGHALAYA/2024-25/140, Dated/दिनांक:

Dated/दिनांक:
09 APR 2024

सेवा में /T₀

1. The A.G.(A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad-500004.
2. The Pr. A.G.(A&E), Andhra Pradesh, Vijaywada-520002.
3. The Pr. A.G.(A&E), Assam, Maidamgaon, Beltola, Guwahati-29.
4. The A.G.(A&E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna-800001.
5. The A.G.(A&E), Chhattisgarh, Raipur-492009.
6. The Pr. A.G.(A&E), Gujarat, Ahmedabad-380009.
7. The A.G. (A&E), Haryana, Plot No.4-5, Sector-33-B, Chandigarh-47.
8. The A.G.(A&E), Himachal Pradesh, Simla-171003.
9. The A.G.(A&E), Jharkhand, Ranchi-834002.
10. The A.G.(A&E), Jammu & Kashmir, Srinagar-190009.
11. The A.G.(A&E), Karnataka, Residency Park Road, Bangalore-1
12. The A.G.(A&E), Kerala, Thiruvananthapuram-695039.
13. The A.G.(A&E) II, Madhya Pradesh, Gwalior-474002.
14. The Pr. A.G.(A&E)-I, Maharashtra, Mumbai-400020.
15. The A.G.(A&E)- II, Maharashtra, Nagpur-440001.
16. The A.G.(A&E), Manipur, Imphal-795001.
17. The Pr. A.G.(A&E), Mizoram, Aizawl-796001.
18. The A.G.(A&E), Nagaland, Kohima-797001
19. The Pr. A.G.(A&E), Odisha, Bhubaneswar.
20. The A.G.(A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh-160017.
21. The Pr. A.G.(A&E), Rajasthan, Jaipur-302005.
22. The A.G.(A&E), Sikkim, Gangtok-737102.
23. The Pr. A.G.(A&E), Tamil Nadu, Chennai-600018.
24. The A.G.(A&E), Tripura, Agartala-799006.
25. The A.G.(A&E)-II, Uttar Pradesh, 20, Sarojini Marg, Prayagraj-211001.
26. The A.G.(A&E), Uttarakhand, Dehradun-248171.
27. The Pr. A.G.(A&E), West Bengal, Treasury Buildings, Kolkata-700001.
28. The Director of Audit & Pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun.
29. The Dy. Director of Accounts/PA-I, Directorate of Accounts (Pension Section) Government of Goa, Panaji, Goa-403 001.

Contd. P/2

काश्याय महाविद्यालय (वि. सं. २०११-१२)

pen/misc

Zur Ruhe

30. The Pr. Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Pension Section, JNB Jan Path, New Delhi-110 001.
31. Director General of Audit, Central Revenues, AGCR Building Indra Prastha Estate, New Delhi-110002.
32. The Officer on Special Duty(PEN), Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, C.P.A.O. Bikaji Cama Place-New Delhi-66.
33. The Pay and Accounts Officer-V, Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi.
34. The Principal Accounts Officer, D.A. "B" Block, Bikash Bhavan, New Delhi.
35. The Director of Treasuries and Accounts, Govt. of West Bengal, New India Assurance Building-3rd Floor, 4, Lyons Range, Kolkata-1.
36. The Director of Accounts and Treasuries, Government of Meghalaya, Shillong.

Subject:-Grant of Dearness Relief to State Government Pensioners/Family Pensioners of Government of Meghalaya, from the existing rate of 39% to 43% w.e.f. 01-01-2024.

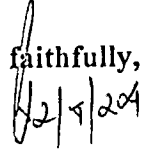
Sir,

Enclosed please find herewith copies of the OM. No. F(PR)-53/2017/66 dated 23-02-2024, issued by the Government of Meghalaya, Finance (Pay Revision) Department which is self explanatory. In this connection, I am to request you to make necessary arrangement to circulate this order to all Treasuries /Sub-Treasuries /Public Sector Banks within the State for further necessary action as per instruction contained therein.

Receipt of the same may please be acknowledged.

Encls:- As stated above.

Yours faithfully,



Senior Accounts Officer

Memò. No./पत्र संख्या: Pension(M)1/F-10/DR/MEGHALAYA/2024-25/

Dated/दिनांक: _____

Copy forwarded for information to :-

The Under Secretary to the Government of Meghalaya, Finance (Pay Revision) Department, Shillong.

Asstt. Accounts Officer

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of **39% to 43%** with effect from **1st January, 2024.**

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of **39% to 43%** with effect from **1st January, 2024.**

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

**GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT**

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.

GOVERNMENT OF MEGHALAYA
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT

The 23rd February, 2024.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dearness Allowance/Dearness Relief.

No.F(PR)-53/2017/66.- The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.F(PR)-53/2017/63, dated 20th December, 2023 and to say that the Governor of Meghalaya is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief payable to all categories of State Government employees/pensioners and family pension holders shall be enhanced from the existing rate of 39% to 43% with effect from 1st January, 2024.

2. These orders shall also apply to the members of the work-charged establishment and casual workers, other than Bungalow Peons, holding posts in the pay levels as admissible to the employees of corresponding categories under the regular establishment/services/ posts.
3. The Dearness Relief under these orders shall remain suspended if the pensioners/family pensioners are employed/re-employed under the State/Central Government or employed/re-employed/permanently absorbed in the State's or Central Government's Company, Corporation, Undertaking or Autonomous Body. It shall, however, be revived after the spell of such employment/re-employment.
4. The payment on account of Dearness Allowance/Dearness Relief involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment on account of the Dearness Allowance/Dearness Relief sanctioned herein shall be debited to the respective heads of accounts from which the employees draw their salary and the pensioners/family pension holders, their pension.

VIJAY KUMAR D,
Commissioner & Secretary to the Govt. of Meghalaya,
Finance Department.